

## Chapter- 5: कांग्रेस प्रणाली: चुनौतियाँ और पुनर्स्थापन

- 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई वे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे, इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन? लेकिन, भारत जैसे नव-स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या ?
- भारत से बाहर के बहुत से लोगो को संदेह थे कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नही इसके अतिरिक्त, इस बात को लेकर भी संदेह थे देश के सामने बहुविध कठिनाइयाँ आन खडी है और न्य नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नही 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस दौर में गरीबी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन आदि प्रमुख समस्याएँ थी
- शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया भारत, चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाईयों से उबरने की कोशिश कर रहा थी 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा
- प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे
- भारत के राजनितिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है दूसरी अध्याय में आप पढ़ चुके कि 1952 के बाद से पूरे देश कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था 1967 के चुनावों में इस प्रतीति में गहरा बदलाव आया

- व्यापक जन-असंतोष और राजनीतिक दलों के धुर्वीकरण के इसी माहौल में लोकसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी
- राजनितिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों स्पस्ट नजर आयगी दो अन्य राज्य में दलबदल के कारण यह पार्टी साकार नहीं बनी सकी जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बनी सकी
- 1967 के चुनावों की एक खास बात दल - बदल भी है इसने राज्यों में सरकारों के बनने - बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को दल में लगाया जाता है 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छेड़ने वाले विधायकों की तीन राज्यों - हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश - में गैर - कांग्रेस सरकारों को बहल करने में अहम भूमिका निभाई
- इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
- सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मीट्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था
- चौदह अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा - महाराजाओं को प्राप्त विशेषधिकार यानी प्रिंसीपैलर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की वी.वी. गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुले आम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालते को कहा
- 1969 के नवम्बर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस ( आग्नेयेशन ) और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस (रिकॉन्सिलिस्ट) कहा जाने लगा था विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया उन्होंने इसे

समाजवादी और पुरातनपन्थी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया

- दूसरी राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की लोकसभा के लिए पाँचवे आम चुनाव 1971 के परवरी माह में हुई
- इस गठबन्धन को लोकसभा की 375 सीट मिली और इसने कुल 48.4 प्रतिशत वोट साहिल किए अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ने 352 सीटें और 44 प्रतिशत वोट हासिल किये अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस (ओ) के उजाड़ से करे : इस पार्टी को महज 16 सीटें मिलीं अपनी भारी -भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया
- 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संगठन उठ खड़ा हुआ 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत -पाक के बीच युद्ध छिड़ गई 1972 के विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली